

रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/95.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, सोमवार, 10 अप्रैल, 1995/20 चैत्र, 1917

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 7 अप्रैल, 1995

संख्या 1-22/95-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन निर्देशावली, 1973 के नियम, 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 (1995 937-राजपत्र/95-10-3-95—1,231. (1565) मूल्य : 1 रुपया ।

का विशेषक संख्यांक 7) को दिनांक 7 अप्रैल, 1995 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरोस्थापित हो गया है, सर्व-साधारण को सूचनायें असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित,-

सचिव ।

1995 का विधेयक संख्यांक 7.

## हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 9) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 1995 है। संक्षिप्त नाम।

1988 का 9 2. हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,— धारा 3 का संशोधन।

(i) खण्ड (जा) में, “या पर्यटकों से भिन्न व्यक्तियों को मौसम (सीजन) के दौरान दैनिक/मासिक किए गए परवास-मुविधा की व्यवस्था करना” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ण) “मौसम” (सीजन) से 15 अप्रैल से 30 जून और 15 सितम्बर से 15 जनवरी तक की अवधि अभिप्रेत है और शेष अवधि “मन्दी का मौसम” होगी ;

(iii) खण्ड (द) में, “जो भारत के किसी भाग या भारत के बाहर से” शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में, निम्नलिखित उप-धारा (4) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(4) कोई भी व्यक्ति पर्यटन क्षेत्र में तब तक होटल नहीं चलाएगा जब तक कि यह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत न हो।”

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (छ) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 12 का संशोधन।

“(छ) यदि होटल चलाने वाला यह सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहता है कि होटल की संरचना का निर्माण क्षेत्र में यथाप्रवृत्त, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन बनाई गई निर्माण उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है।”

1977 का 12

1994 का 4

1994 का 13

1994 का 12

धारा 13 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 13 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

“(ज) यदि होटल चलाने वाला हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना होटल की संरचना में परिवर्तन करता है।”

धारा 16 का संशोधन। 6. मूल अधिनियम की धारा 16 के खण्ड (क) में,—

(i) “होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों या अन्य ग्राहकों से” शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) “खान-गान या ठहरने या दोनों” शब्दों का लोप किया जाएगा और उनके स्थान पर “ठहरने” शब्द रखा जाएगा।

धारा 42 का संशोधन। 7. मूल अधिनियम की धारा 42 में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

धारा 55 का लोप। 8. मूल अधिनियम की धारा 55 का लोप किया जाएगा।

### उद्देश्यों और कार्यों का कथन

पर्यटन अत्याधिक महत्व प्राप्त कर रहा है और अब इसे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन रूप से नियमित क्षमता वाले मुख्य कर्मक्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश में अपने निवासियों को बहुसंख्या में आजीविका और समृद्धि को व्यवस्था करने के लिए इस उद्योग के विकास के अत्याधिक अवसर हैं। विद्यमान हिमाचल प्रदेश पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1988 को, उदारीकरण और निजीकरण की तेज गति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए, अपर्याप्त पाया गया है। अत्याधिक प्रतियोगी और आक्रमणशील वातावरण में जीवित और फलने-फूलने के लिए पर्यटन उद्योग में अधिक लचीलापन, प्रत्यायोजन और विश्वास का होना अनिवार्य है। इसलिए इसके उपबन्धों को नया रूप देना आवश्यक हो गया है। उदाहरण के तौर पर, वर्तमान अधिनियम में यथाविहित पर्यटन मौसम (सीजन) कालावधि असम्यक् रूप से लम्बी है। कड़ी सर्दी और लम्बे वर्षाकाल के कारण, पर्यटन मौसम (सीजन) वास्तव में वर्ष में लगभग छः मास तक ही सीमित है, जिसमें गर्मी, शरदकाल और सर्दी का मौसम आता है। यह भी महसूस किया गया है कि प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का आनुकूलिक नवीकरण होटल/रेस्तरां स्वामियों के लिए एक अनावश्यक परेशानी है, जिन द्वारा पहले ही अधिनियम की धारा 12 (घ) के अधीन अनुकरण और उचित व्यापार आचरण के कुछ विहित मानदण्डों का पालन करना अपेक्षित है। इसलिए नए अधिनियम में इन उपबन्ध का लोप किया जाना वांछित होगा। इसी प्रकार, होटल चलाने वालों द्वारा पर्यटन मौसम (सीजन) के दौरान स्थानीय निवासियों को वासमुविद्या उपलब्ध न कराने के विद्यमान उपबन्ध भी अनुचित और अनावश्यक हैं और इसका लोप किया जाना जरूरी है। अधिनियम की धारा 16 (क) के विद्यमान उपबन्ध को भी, जिस द्वारा पर्यटन विभाग से न केवल कमरे का टैरिफ, बल्कि खाद्य पदार्थों की दरें भी नियत करना अपेक्षित है, उपान्तरित करने का प्रस्ताव है। यह बात महत्वपूर्ण है कि सम्पूर्ण राज्य में फैले हुए विभिन्न प्रकार के रेस्तरां, होटल, ढाबे और अन्य जल-भान स्थलों में परोसे जाने वाले खाद्य-पदार्थों की दरें नियत करना पर्यटन विभाग का कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, विद्यमान स्थानीय उप-विधियों की पूर्ण अवज्ञा में राज्य में होटलों की अनियोजित आकस्मिक वृद्धि की समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक बनाया जाना आवश्यक हो गया है कि होटल चलाने वाले केवल उन्हीं परिसरों में होटल चलाएं जिनका निर्माण उस क्षेत्र में प्रवृत्त निर्माण उप-विधियों के अनुसार किया गया हो तथा सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किए गए हों। होटल/रेस्तरां स्वामियों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे उन पर वाणिज्यिक क्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व अपनी सम्पत्तियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के पास सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत करवाएं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,  
मुख्य मंत्री।

शिमला:

7 अप्रैल, 1995

### वित्तीय जापन

विधेयक के उपबन्धों को अधिनियमित किए जाने पर, विद्यमान सरकारी तन्त्र को ग्राह्यता में कार्यन्वित किया जाएगा। अतः विधेयक के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर राजकोष में कोई अतिरिक्त व्यय उत्पन्न नहीं किया जाएगा। विधेयक के खण्ड 8 द्वारा धारा 55 का संशोधन किए जाने को फलस्वरूप राज्य सरकार को मूल अधिनियम के अधीन प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तर्गत पर रजिस्ट्रार के तथ्यांक के लिए प्रभावी फीस का छोड़ना पड़ेगा। इस समय कोई ऐसी फीस प्रभावित नहीं की जा रही है। अतः राज्य के राजस्व में कोई हानि होना सम्भाव्य नहीं है।

### प्रत्याशोजित विधान सम्बन्धी जापन

—शून्य—

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

Bill No. 7 of 1995.

**THE HIMACHAL PRADESH REGISTRATION OF TOURIST TRADE  
(AMENDMENT) BILL, 1995**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

**BILL**

*to amend the Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988  
(Act No. 9 of 1988).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade (Amendment) Act, 1995.

Short title.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988 (hereinafter called the principal Act),—

Amendment of section 3.

(i) in clause (j), the words “or providing accommodation during the season on daily/monthly rent to persons other than tourists” shall be omitted.

(ii) for clause (o), the following shall be substituted, namely:—

“(o) “season” means the period from 15th April to 30th June; and from 15th September to 15th January; and the rest of the period will constitute “off season”; and

(iii) in clause (r), the words “from any part of India or outside India” shall be omitted.

3. In section 10 of the principal Act, the following sub-section (4) shall be added, namely:—

Amendment of section 10.

“(4) No person shall operate a hotel in a tourist area unless it is registered in accordance with the provisions of this Act.”

4. In section 12, after clause (f) of the principal Act, the following clause (g) shall be added, namely:—

Amendment of section 12.

“(g) if the hotel-keeper fails to produce the proof that the structure of the hotel has been built-up in accordance with the building bye-laws made under the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, or of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, or of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, as in force in the area.”

5. In section 13 of the principal Act, for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of section 13.

“(h) if the hotel-keeper makes structural changes in the hotel without the approval of the Development Authority constituted under

12 of 1977  
4 of 1994  
13 of 1994  
12 of 1994

the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 12 of 1977  
or any other local authority concerned."

Amendment  
of section 16.

6. In section 16 of the principal Act, in clause (a), for the words "board or lodge or for both from persons staying therein or from other customers", the word "lodge" shall be substituted.

Amendment  
of section 42.

7. In section 42 of the principal Act, the Explanation shall be deleted.

Omission of  
section 55.

8. Section 55 of the principal Act shall be omitted.



## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Tourism is gaining great importance and is now recognised as one of the major thrust areas in Himachal Pradesh with invisible exports potential. Himachal Pradesh has a tremendous scope for developing this industry to provide employment and prosperity to a large number of its inhabitants. The existing Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988 has been found deficient to meet the challenge posed by the new spurt of liberalisation and privatisation, which calls for greater flexibility, delegation and trust in the tourism industry for it to survive and thrive on a highly competitive and aggressive environment. Thus, the need has arisen to recast its provisions. For instance, the duration of the tourist season as prescribed in the extant Act is unduly long. Due to severe winters and long rainy spell, the tourist season is actually limited to just about 6 months in a year, covering the summer, autumn and winter season. It has also been felt that successive renewal of registration after every 3 years is an un-necessary harassment to the hotel/restaurant owner who is already required to adhere to certain prescribed norms of upkeep, and fair trade practices under section 12(d) of the Act. It would, therefore, be desirable to delete this provision in the new Act. Similarly, the existing provisions restricting the hoteliers from providing accommodation to the local residents during the tourist season are also unfair and un-necessary and, therefore, need to be deleted. It is also proposed to modify the existing provision in section 16(a) of the Act, whereby the Department of Tourism is not merely required to fix the room tariff but the rates of eatables also. It will be appreciated that it is not the job of the Department of Tourism to fix the rates of eatables served in a variety of Restaurants, Hotels, Dhabas and other eating places spread throughout the State. Moreover, to tackle the problems of unplanned mushroom growth of hotels in the State in utter defiance of existing local bye-laws, it has been found necessary to make it obligatory for the hotel-keeper to operate the hotels only on premises constructed strictly in accordance with the building bye-laws in force in the area and duly approved by the local authorities concerned. It would also be obligatory for the hotel/restaurant owners to get their properties duly registered with the Department of Tourism, Government of Himachal Pradesh, before being permitted to commence commercial operations thereon.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SHIMLA:

*The 7th April, 1995.*

VIRBHADRA SINGH,  
Chief Minister.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

The provisions contained in the Bill, when enacted, will be implemented through the existing Government machinery and thus, for the implementation of the provisions of the Bill, no additional expenditure will be incurred out of the State Exchequer. Consequent upon the omission of section 55, *vide* clause 8 of the Bill, the State Government will have to forego the fee chargeable, at an interval of every three years for the renewal of registrations under the principal Act. At present no such fee is being charged, hence no loss is likely to occur to the State revenue.

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-